भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3022
11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता

3022. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सांख्यिकीय सुदृढीकरण हेतु सहायता (एसएसएस) उप-योजना के तहत समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के अनुसार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कितनी निधि जारी की गई और चरण 2026-31 के लिए हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ हुई वार्ता, आयोजित किए गए सम्मेलनों और 'एसएसएस 2.0' के पुनर्गठन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सांख्यिकीय प्रणालियों और उप-राज्य स्तर पर डेटा सृजन संबंधी उक्त उप-योजना के प्रभाव के संबंध में किए गए आकलन, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) और (ख)**:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता (एसएसएस) उप-योजना सहित, क्षमता विकास योजना के लिए, 2026-31 की अवधि हेतु व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ज्ञापन का मसौदा तैयार किया है, जिसे व्यय विभाग की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। चूँकि ईएफसी अवधि अभी प्रारम्भ नहीं हुई है, इसलिए 2026-31 की अवधि के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

एमओएसपीआई ने राज्य सांख्यिकीय प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए मौजूदा एसएसएस दिशा-निर्देशों के पुनर्गठन (एसएसएस 2.0) की प्रक्रिया भी शुरू की है, जिसमें आधुनिक डेटा प्रौद्योगिकियों को अपनाना, सांख्यिकीय कार्मिकों की क्षमता निर्माण तथा सुदृढ़ उप-राज्य संकेतकों का विकास शामिल है। एसएसएस योजना के अंतर्गत उनके कार्यान्वयन अनुभव के आधार पर सुझाव प्राप्त करने हेतु एमओएसपीआई के प्रभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श आयोजित किए गए।

इन विचार-विमर्श के आधार पर एसएसएस 2.0 दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया गया तथा टिप्पणियों हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं एमओएसपीआई के प्रभागों को परिचालित किया गया, जिनमें से 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। मसौदा दिशा-निर्देशों पर 25–26 सितम्बर 2025 को चंडीगढ़ में आयोजित केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकीय संगठनों के सम्मेलन (सीओसीएसएसओ) के दौरान भी चर्चा की गई।

(ग)**:** एमओएसपीआई ने मेसर्स इंडिया लिमिटेड के माध्यम से एसएसएस उप-योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराया। मूल्यांकन में निष्कर्ष निकाला गया कि इस उप-योजना ने राज्य सांख्यिकीय प्रणालियों में संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ किया है, डेटा प्रसार की प्रथाओं में सुधार किया है तथा आधुनिक सांख्यिकीय पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित किया है। मूल्यांकन में यह भी रेखांकित किया गया कि जनशक्ति को सुदृढ़ करने, निधि प्रवाह तंत्र को सुव्यवस्थित करने तथा राज्यों में एक समान निगरानी एवं फीडबैक रूपरेखा स्थापित करने की आवश्यकता है। मूल्यांकन में यह उल्लेख किया गया कि उप-योजना राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनी हुई है तथा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति में योगदान देती है।

****